

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

1. अपील संख्या 2695 / 2016 / झुञ्जुनू
2. अपील संख्या 2696 / 2016 / झुञ्जुनू
3. अपील संख्या 2697 / 2016 / झुञ्जुनू
4. अपील संख्या 2700 / 2016 / झुञ्जुनू
5. अपील संख्या 2701 / 2016 / झुञ्जुनू

वाणिज्यिक कर अधिकारी,
प्रतिकरापवंचन, झुञ्जुनू।

.....अपीलार्थी.

बनाम

मैसस अंकुश मार्केटिंग प्रा०लि०, चिडावा।

.....प्रत्यर्थी

खण्डपीठ

श्री मदन लाल, सदस्य
श्री मदन लाल मालवीय, सदस्य

उपस्थित :

श्री डी.पी.ओझा, उप राजकीय अभिभाषक।

.....अपीलार्थी की ओर से

श्री वी.सी.सोगानी, अभिभाषक।

.....प्रत्यर्थी की ओर से.

निर्णय दिनांक : 18.05.2017

निर्णय

1. उपर्युक्त सभी पाचों अपीलें अपीलार्थी राजस्व द्वारा अपीलीय प्राधिकारी, वाणिज्यिक कर, बीकानेर (जिसे आगे "अपीलीय अधिकारी" कहा जायेगा) द्वारा पारित अपीलीय आदेशों के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी है, जिसमें अपीलीय अधिकारी ने वाणिज्यिक कर अधिकारी, प्रतिकरापवंचन झुञ्जुनू (जिसे आगे "सशक्त अधिकारी" कहा जायेगा) द्वारा राजस्थान राज्य में स्थायी क्षेत्रों में माल के प्रवेश पर कर अधिनियम, 1999 (जिसे आगे "अधिनियम" कहा जायेगा) की धारा 15(1)(2), 34(ए) एवं 35(1)(ए) के अन्तर्गत पारित आदेशों के जरिये कायम की गयी मांग राशियों में से धारा 15(2) के तहत आरोपित शास्ति के बिन्दु पर अपील स्वीकार किये जाने को अधिनियम की धारा 16 के तहत विवादित किया है। उनका विवरण निम्न तालिका अनुसार है :-

अपील सं.	अपी.अधि. की अपी. सं.	अपी.आदे.दि.	कर निर्धा. आदेश दिनांक	क.नि. वर्ष	शास्ति अंतर्गत धारा 15(2)
2695 / 16	118 / अपीलस बीकानेर / प्रवेश कर	30.09.16	18.04.16	12-13	45,875
2696 / 16	120 / अपीलस बीकानेर / प्रवेश कर	30.09.16	18.04.16	14-15	38,92,109
2697 / 16	121 / अपीलस बीकानेर / प्रवेश कर	30.09.16	18.04.16	15-16	21,888
2700 / 16	119 / अपीलस बीकानेर / प्रवेश कर	30.09.16	18.04.16	13-14	1,54,139
2701 / 16	117 / अपीलस बीकानेर / प्रवेश कर	30.09.16	18.04.16	10-11	61,865

2. इन पांचों अपील प्रकरणों के तथ्य एवं विवादित बिन्दु समान होने के कारण इनको एक ही आदेश से निर्णित किया जाकर निर्णय की एक-एक प्रति प्रत्येक पत्रावली पर पृथक-पृथक रखी जा रही है।

3. प्रकरणों के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि व्यवहारी के व्यवसाय स्थल का सर्वेक्षण सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, प्रतिकरापवंचन प्रथम, झुञ्जुनू द्वारा किये जाने पर पाया कि उसके द्वारा खेतडी में माईनिंग का कार्य किया जाता है एवं उसके द्वारा राज्य के बाहर से टायर एण्ड ट्यूब स्पेयर्स / पाटर्स आयात किये गये, आयात किये गये माल पर प्रवेश कर का भुगतान नहीं किया गया। व्यवहारी ने स्वयं इनका राज्य में उपयोग / उपभोग किया है, व्यवहारी पर राज्य में प्रवेश कर का दायित्व मानते हुए अभियोग स्थापित करते हुए पत्रावली सशक्त अधिकारी को स्थानान्तरित की गई। सशक्त अधिकारी ने पाया कि व्यवहारी द्वारा टायर एण्ड ट्यूब इत्यादि प्रवेश करयोग्य वस्तुएं राज्य के बाहर से खरीद की गई हैं तथा वेट 47 एवं सी फार्म द्वारा माल क्रय करते हुए उपभोग किया है, जिस पर 4 प्रतिशत की दर से कर दायित्व निर्धारित करते हुए प्रवेश कर, धारा 34ए के तहत ब्याज एवं धारा 35(1)(ए) के तहत शास्ति तथा धारा 15(2) के तहत निर्धारित कर की ढेढगुना शास्ति आरोपित की गई। उक्त आदेशों से व्यथित होकर व्यवहारी द्वारा

लगातार.....2

अपीलें अपीलीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत की गई जिनका निस्तारण करते हुए अपीलीय अधिकारी ने करदेयता व ब्याज के बिन्दु पर अपील अस्वीकार की परन्तु एक्सकेवेटर के पार्टस/स्पेयर पार्टस पर करारोपण हेतु प्रकरण प्रतिप्रेषित किया गया है, लेकिन करयोग्य माल की प्रविष्टि उजागर नहीं करने पर अधिनियम की धारा 15(2) के तहत आरोपित शास्ति को अपास्त किया एवं व्यवहारी की अपीलें आंशिक स्वीकार की। उक्त आदेशों के विरुद्ध विभाग द्वारा यह अपीलें अधिनियम की धारा 83 के तहत कर बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत की गई है।

4. उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

5. अपीलार्थी विभाग की ओर से विद्वान उप राजकीय अभिभाषक ने निवेदन किया कि व्यवहारी द्वारा राज्य के बाहर से टायर, ट्यूब्स, लुब्रीकेन्ट, स्टील स्ट्रक्चरल स्पेयर पार्टस का आयात किया जाता है, जिस पर प्रवेश कर देय बनता है। व्यवहारी द्वारा प्रवेश कर अदा नहीं किया गया एवं अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन किया है। अतः उन्होंने व्यवहारी पर आरोपित कर व ब्याज को अपीलीय अधिकारी को यथावत रखा है, अतः आरोपित अंतर्गत अधिनियम की धारा 15(2) की शास्ति को उचित बतलाते हुए शास्ति के बिन्दु पर विभाग की अपीलें स्वीकार करने का निवेदन किया।

6. व्यवहारी की ओर से विद्वान अभिभाषक ने कथन किया कि व्यवहारी कम्पनी खेतडी में माईनिंग का कार्य करती है एवं इस कार्य में मशीनरी का उपयोग किया जाता है। तर्क दिया कि माईनिंग कार्य हेतु LH-307(LHD) and two number of EJC-305, (LPDT) "सेन्डिव एशिया लि0 कम्पनी के साथ अण्डरग्राउण्ड माईनिंग का कार्य कोलीहान कॉपर माईन्स तथा खेतडी कॉपर कॉम्प्लेक्स जिला झुञ्जुनू में किया जा रहा है। व्यवहारी द्वारा माईनिंग कार्य (LHD-Load Haul, Dump, LPDT-Low Profile Dump Truck - LHD Dugs the ore and puts in LPDT dumps it into an dumping area within the enclosed & mining premises.) आधुनिक मशीनों से किया जाता है तथा इनका उपयोग आम पब्लिक रोड पर नहीं किया जा सकता है एवं इन मशीनों को माईनिंग कार्य समाप्त होने पर एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए रोड का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता यानि ऑन रोड चलाकर नहीं ले जा सकते, बल्कि इनको अन्य भारी वाहन जैसे ट्रेलर में लोड करके ही ले जाया जाता है। इन मशीनों की सुरक्षा एवं रख-रखाव हेतु "डीजीएमएस" (डायरेक्टर जनरल ऑफ माइन्स सेफ्टी) द्वारा अनेक शर्तें निर्धारित की गई हैं, जिनकी पालना करनी होती है। उन्होंने आगे तर्क दिया कि व्यवहारी फर्म का सर्वे दिनांक 01.06.2015 को सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, घट-प्रथम, एई, झुञ्जुनू द्वारा किया गया जिसमें उनके द्वारा निष्कर्ष निकाला गया कि कम्पनी द्वारा अर्थ मूविंग एवं माईनिंग मशीनरी (स्पेयर पार्टस) टायर, ट्यूब, लुब्रीकेन्ट, स्टील स्ट्रक्चर का आयात राज्य के बाहर से किया है, जिस पर उसके द्वारा प्रवेश कर नहीं चुकाया गया है। अतः उनके द्वारा कर, ब्याज एवं शास्तियों का आरोपण किया गया जिसकी अपील करने पर कर व ब्याज को यथावत रखा गया है सिवाय एक्सकेवेटर के स्पेयर पार्टस/पार्ट पर करारोपण हेतु प्रतिप्रेषित किया गया है, व्यवहारी पर आरोपित शास्ति अधिनियम की धारा 15(2) को अपीलीय अधिकारी द्वारा अपास्त किया गया है, जो विधिक है। अतः उन्होंने अपीलीय अधिकारी के आदेशों को उचित बतलाते हुए विभाग द्वारा प्रस्तुत अपीलों को अस्वीकार करने का निवेदन किया गया। अपने तर्कों के समर्थन में निम्नांकित न्यायिक दृष्टान्त उद्धरित किये गये :-

1. मै0 हिन्दुस्तान स्टील लि0 बनाम स्टेट ऑफ उडीसा (1970) 25 एसटीसी 211(एससी)
2. मै0 विजय होजरी मिल्स बनाम स्टेट ऑफ राज0 (1980) 45 एसटीसी 345 (राज डीबी)
3. एसीटीओ बनाम कुमावत उद्योग (1995) 97 एसटीसी 238 (राज. एसबी)
4. हालेट पेकर्ड इण्डिया सेल्स प्रा0लि0, सी-185 सिंहल ऑटोमेटिक्स, वीकेआई, जयपुर बनाम सीटीओ ज़ोन एंटीवीजन-द्वितीय दिनांक 16.09.09 25 टीयूडी 189 में भी यह अभिनिर्धारित किया गया है, कि यदि खरीद बिक्री के संव्यवहार लेखा पुस्तिकाओं में दर्ज है तो शास्ति का आरोपण विधिक नहीं है।
5. माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय श्रीकृष्णा इलेक्ट्रिकल्स बनाम तमिलनाडू राज्य एवं अन्य (2010) 26 टैक्स अपडेट 01

↓

↓

7. उभयपक्षीय बहस सुनी गयी। रिकॉर्ड का परिशीलन किया गया एवं प्रस्तुत न्यायिक व्यवस्थाओं का सुसंगत अध्ययन किया गया। प्रकरण में व्यवहारी द्वारा आयातित माल अर्थ मूविंग मशीन एवं माइनिंग मशीनरी से संबंधित जो पार्टस / स्पेयर पार्टस व्यवहारी द्वारा राज्य के बाहर से आयात किये गये हैं, उनको सशक्त अधिकारी द्वारा मोटर व्हीकल के पार्टस मानकर उन पर प्रवेश कर आरोपित किया है एवं अपीलीय अधिकारी ने इस पर प्रवेश कर व ब्याज की पुष्टि भी की है। परन्तु अपीलीय अधिकारी ने अपने आदेश में माना है कि अर्थ मूविंग एवं माइनिंग मशीनरी (Excavators) का उपयोग केवल माइनिंग कार्य हेतु ही किया जाता है तथा इन मशीनों हेतु उक्त पार्टस/स्पेयर पार्टस मंगवाये गये हैं, जो कभी भी रोड पर नहीं चलती है तथा कार्य समाप्ति उपरान्त उन्हें ट्रैलर में डालकर ही अन्यत्र स्थान पर परिवहनित किया जाता है। अतः एक्सकेवेटर के पार्टस/स्पेयर पार्टस के आयात पर प्रकरणों में कर व ब्याज के बिन्दु पर अपीलीय अधिकारी द्वारा प्रकरण सशक्त अधिकारी को प्रतिप्रेषित किये गये हैं। परन्तु इन समस्त वस्तुओं के प्रवेश को उजागर नहीं करने पर अधिनियम की धारा 15(2) के तहत आरोपित शास्तियों को अपास्त किया गया है। विभाग द्वारा पांचों अपीलों में केवल शास्ति को अपास्त करने को चुनौती दी गई है, अतः शास्ति के बिन्दु पर प्रकरणों का निस्तारण किया जा रहा है। शास्ति आरोपण के संबंध में अधिनियम की धारा 15(2) की उपपति निम्नानुसार है :-

"In making an assessment under sub-section (1) the assessing authority may, if it is satisfied that the escape from assessment is due to willful non disclosure of the entry of such goods by the dealer, direct him to pay, in addition to the tax assessed under sub section (1), a penalty not exceeding one and a half times the tax so assessed.

Provided that no penalty under this sub section shall be directed to be paid unless the dealer affected has had a reasonable opportunity of showing cause against such penalty."

प्रकरणों में समस्त संव्यवहार व्यवहारी द्वारा अपनी लेखा पुस्तकों में नियमित रूप से संधारित किया जा रहा है एवं अधीनस्थ अधिकारियों के समक्ष आयातित माल के बिल्स, बिल्टियां एवं लेखा पुस्तकें प्रस्तुत की गई हैं, जिससे व्यवहारी की जानबूझकर करापवंचना की नीयत सिद्ध नहीं होती है।

शास्ति के बिन्दु पर माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय (2009) 23 वीएसटी 249 श्री कृष्णा इलेक्ट्रीकल्स बनाम स्टेट ऑफ तमिलनाडू, टैक्स अपडेट वोल्यूम 43 पार्ट 4 पेज 158 का संक्षिप्त उल्लेख निम्नानुसार है:-

"So far as the question of penalty is concerned the items which were not included in the turnover were found incorporated in the appellant's account books, where certain items which are not included in the turnover are disclosed in the dealer's own account books and the assessing authorities includes these items in the dealers' turnovers disallowing the exemption penalty cannot be imposed. The penalty levied stands set aside."

माननीय उच्चतम न्यायालय के न्यायिक दृष्टांत के अनुरूप व्यवहारी के बिना कर चोरी की मंशा प्रमाणित होने के आधार पर, आरोपित शास्ति को अपीलीय अधिकारी द्वारा अपास्त किये जाने में कोई त्रुटि प्रतीत नहीं होती है। अतः शास्ति के बिन्दुओं पर अपीलीय अधिकारी के निर्णयों की पुष्टि की जाती है एवं राजस्व द्वारा प्रस्तुत पांचों अपीलों इस सीमा तक अस्वीकार की जाती हैं।

13. परिणामस्वरूप राजस्व द्वारा प्रस्तुत पांचों अपीलों अस्वीकार की जाती है।

निर्णय सुनाया गया।

(मदन लाल मीलवीय)
सदस्य

(मदन लाल)
सदस्य